प्रेस विज्ञप्ति

'राज्य के माननीय विधायकगणों के साथ बजट पूर्व कार्यशाला'
जयपुर 5 मार्च 2016

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) द्वारा राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान के सहयोग से पंत कृषि भवन, जयपुर मे राज्य के माननीय विधायकगणों के साथ 'राज्य स्तरीय बजट पूर्व कार्यशाला' आयोजित की गई, इस कार्यशाला में राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा), हीरा लाल रैगर (निवाई) गोवर्धन जी वर्मा (धोड), झाबर सिंह (श्रीमाधोपुर), धीरज गुर्जर (जहाजपुर) सहित विभिन्न संस्थाओं एवं मीडिया के करीब 37 प्रतिनिधी शामिल हुए। इस कार्यशाला में प्रमुख रूप से निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. राज्य की अर्थव्यवस्था
2. पिछले वर्ष तक बजट की स्थिति
3. राज्य की वित्तिय स्थिति
4. राज्य में बच्चों हेतु बजट

कार्यशाला के आरंभ में चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा हुई। बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र के नेसार अहमद ने बताया कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को केन्द्रीय करों में बढी भागीदारी के बावजूद राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि में शुद्व रुप से कोई बढोतरी नहीं हुई है। एक तरफ जहां राज्य को केन्द्रीय करों से मिलने वाला हिस्सा बढा है वहीं केन्द्रीय सहायता तथा अनुदान के अंतर्गत मिलने वाली राशि में कटौती हुई है। परिणामस्वरुप केन्द्र से प्राप्त होने वाली कुल राशि में कोई बढोतरी नहीं हुई है।

इसके बाद प्रदेश की वर्तमान आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति पर चर्चा हुई जिसमें कहा गया कि सरकार ने इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कुल आयोजना खर्च तथा कुल पूंजीगत खर्च में कोई बढोतरी नहीं की। बाद में सरकार के घाटे तथा कुल कर्ज पर भी चर्चा हुई।
इसके बाद राज्य में बच्चों के लिये कुल बजट पर प्रस्तुती दी गयी जिसमें पता चला कि राज्य में जहां 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी करीब 47 प्रतिशत है वहीं राज्य बजट का मात्र करीब 18 से 20 प्रतिशत ही बच्चों के लिये आवंटित होता है जिसमें से करीब 80 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता है। जबकि स्वास्थ्य पर करीब 10 प्रतिशत तथा पोषण पर करीब 8 प्रतिशत आवंटित किया जा रहा है। इसके विपरित बाल संरक्षण (बाल मजदूरी, यौन उत्पीड़न, समेकित बाल संरक्षण योजना आदि) पर बच्चों के कुल बजट का करीब 1 प्रतिशत से कम आवंटित होता है। बाल संरक्षण का कुल बजट वर्ष 2014–15 के प्रस्तावित बजट में करीब 168.8 करोड़ रु. से घटकर वर्ष 2015–16 के प्रस्तावित बजट में करीब 111.3 करोड़ रु. रह गया। पोषण पर कुल आवंटन वर्ष 2014–15 के प्रस्तावित बजट में 2719 करोड़ रु. था जो वर्ष 2015–16 के प्रस्तावित बजट में घटकर करीब 2355 करोड़ रु. रह गया।

P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur- 302005
Tel./Fax : (0141) 2385254
E-mail : info@barcjaipur.org Website : www.barcjaipur.org

कार्यशाला में बजट बनाने की प्रक्रिया तथा इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी पर भी चर्चा हुई। नेसार अहमद ने कहा कि अक्टुबर से जनवरी तक जब बजट बनाने की प्रक्रिया चल रही होती है तब विभिन्न संस्थाएं तथा जनप्रतिनिधी सरकार तक अलग– अलग माध्यमों से अपनी बात रख सकते हैं। उपस्थित विधायकों ने बताया कि इस वर्ष भी उनसे बजट के संदर्भ में सरकार ने प्राथमिकताएं मांगी थी तथा वेबसाईट के माध्यम से भी आमजनता से सुझाव मांगे थे।

कार्यशाला में विधायकों ने बजट से संबंधित कुछ सुझाव रखे जिसमें वित्त विधेयक एवं विनियोग विधेयक को अलग–अलग दिन पेश करने का सुझाव दिया ताकि वित्त विधेयक में प्रतिपक्ष को अपने सुझावों को भी रखने को अवसर मिल सके। बार्क की ओर से सुझाव दिया गया कि मुख्यमंत्री सूचना तंत्र (सी.एम.आई.एस.) को आम जनता के उपयोग के लिये खोला जाये। साथ ही हर विभाग अपनी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को त्रेमासिक आधार अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर जोर दिया। विजय गोयल तथा अन्य संस्था प्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं के क्रियांवयन में सुधार तथा प्रभावी निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया। बाल संरक्षण के लिये बजट बढाने तथा राज्य में पोषण की निती बनाने के सुझाव भी रखे गये।

उपस्थित विधायकगणों ने यह सुझाव दिया कि बार्क को यह कार्यशाला जनवरी माह में आयोजित करनी चाहिये ताकि कार्यशाला में उभरे सुझावों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। कार्यशाला के अंत में बार्क के नेसार अहमद ने सभी विधायकगणों एवं संस्था प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया तथा इन चर्चाओं से प्राप्त सुझावों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करने का आश्वासन दिया।

धन्यवाद

नेसार

नेसार अहमद
समन्वयक

P-1, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur- 302005
Tel./Fax : (0141) 2385254
E-mail : info@barcjaipur.org Website : www.barcjaipur.org